बिहार विधान परिषद्

185वां सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग – 4

वृहस्पतिवार, तिथि 11 फाल्गुन, 1938 (श.)
02 मार्च, 2017 ई.

प्रश्नों की कुल संख्या – 10

1.	वित्त विभाग	-	-	02
2.	श्रम संसाधन विभाग	-	-	01
3.	समाज कल्याण विभाग	-	-	01
4.	लघु जल संसाधन विभाग	-	-	01
5.	योजना एवं विकास विभाग	-	-	01
6.	पर्यावरण एवं वन विभाग	-	-	01
7.	गृह (आरक्षी) विभाग	-	-	02
8.	उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	-	-	01
			कुल योग	– 10

मौलिक अधिकार से वंचित

29. **श्री सतीश कुमार** : क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि मो. जान मियां, ग्राम-इन्द्रगाद्दी, थाना-संग्रामपुर, जिला-पूर्वी चम्पारण की बेटी की शादी तारीख 05.12.16 को होना निश्चित था;

(ख) क्या यह सही है कि दिनांक 19.11.16 को मो. जान मियां अपनी बेटी की शादी हेतु 1,50,000 (एक लाख पचास हजार) रु. की निकासी करने गये थे, तदुपरांत उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के मैनेजर (शाखा प्रबंधक) द्वारा कागजातों की मांग की गई, जिसके बाद मो. जान मियां द्वारा शाखा प्रबंधक, उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, दरियापुर, पूर्वी चम्पारण के नाम आवेदन पत्र, आधार कार्ड, शादी का कार्ड एवं उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के खाता सं.-1002681010001540, पुराना नं.- बचत खाता सं.-3286 की सच्ची प्रतिलिपि को उपलब्ध कराया गया, मगर बैंक द्वारा रुपये शादी के लिए नहीं दिए गए;

(ग) क्या यह सही है कि उत्तर क्षेत्रीय बिहार ग्रामीण बैंक, शाखा दरियापुर ने टालमटोल की नीति अपनाते हुए उसने क्षेत्रीय प्रबंधक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय (5) को दिशा-निर्देश हेतु दिनांक 23.11.16 को पत्र लिखा;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार मो. जान मियां की बेटी की शादी हेतु बैंक खाता में रु. रहते 1,50,000/ रु. नहीं दिया, जिससे काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा तथा बैंक के नियमविरुद्ध एवं आम आदमी के मौलिक अधिकार से वंचित रखने वाले शाखा प्रबंधक एवं क्षेत्रीय प्रबंधक, पूर्वी चम्पारण द्वारा किए गये इस कुकृत्य कार्य हेतु कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

सूची उपलब्ध करवाने पर विचार

30. **श्री मंगल पाण्डेय** : क्या मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि सात निश्चय के आर्थिक हल युवाओं को बल के कार्यक्रम के तीन अवयव स्वयं सहायता भत्ता योजना, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना एवं कुशल युवा कार्यक्रम का शुभारंभ 02.10.2016 से किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि सरकार के द्वारा घोषित इतनी महत्वपूर्ण घोषणा की शुरुआत के बाद जिलावार बेरोजगार युवाओं को सहायता दिया जाना है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार बीते महीने के बाद से कितने लोगों को उपर्युक्त कार्यक्रम को मिलाकर सुविधा पहुंचा पायी, इसकी सूची उपलब्ध कराना चाहती है?

नये आंगनबाड़ी की स्थापना

31. **श्री लाल बाबू प्रसाद** : क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य में वर्तमान में 91 हजार 677 आंगनबाड़ी केन्द्र हैं, जिनमें मात्र 86 हजार आंगनबाड़ी केन्द्र का ही संचालन किया जा रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा सहायिका एवं सेविका नियुक्ति नियमावली को संशोधित किया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार नए आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

तालाब जीर्ण-शीर्ण

32. **श्री नीरज कुमार** : क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पटना जिला के मालपुर पंचायत के शेरपुर ग्राम में मिडिल स्कूल के पीछे सरकारी तालाब जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पड़ा है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार वर्णित तालाब का जीर्णोद्धार कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

बेरोजगारी भत्ता का भुगतान

33. **प्रो. नवल किशोर यादव** : क्या मंत्री, योजना एवं विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य में हर काम पूरी तैयारी से करने का दावा करने वाले तथा 02 अक्टूबर, 2016 से प्रारंभ बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ तीन महीने बाद भी किसी को नहीं मिल रहा है जिससे शिक्षित बेरोजगारों में क्षोभ व्याप्त है;

(ख) क्या यह सही है कि चालू वित्तीय वर्ष में 2040 करोड़ खर्च कर 17.81 लाख युवकों को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने का लक्ष्य रखा गया है किन्तु अबतक मात्र 30 हजार आवेदन को ही मंजूरी दी गई है तथा 5 लाख छात्रों को 4 लाख तक कर्ज दिलाने की स्टूडेन्ट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत भी मात्र 4 हजार आवेदन ही आ पाए हैं, फिर भी विभाग के पास शराबबंदी के बाद पैसे की कमी दर्शाकर मैट्रिक व इंटर पास युवकों को योजना लागू करने में विफलता साबित हो रही है, जिससे बेरोजगारों में असंतोष व्याप्त है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शिक्षित बेरोजगारों को अविलम्ब बेरोजगारी भत्ता देने एवं अनावश्यक शर्त्तों को थोप व योजना को समय-सीमा के भीतर भत्ता नहीं देने वालों पर विभागीय कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि नहीं तो क्यों?

पहाड़ियों का सर्वांगीण विकास

34. **श्री कृष्ण कुमार सिंह** : क्या मंत्री, पर्यावरण एवं वन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि गया शहर की पहाड़ियां धार्मिक एवं पौराणिक रूप से विशिष्ट पहचान एवं महत्व वाली हैं;

(ख) क्या यह सही है कि सरकार की अकर्मण्यता एवं अनदेखी के कारण पहाड़ियां अतिक्रमण का शिकार हो रही हैं;

(ग) क्या यह सही है कि ब्रह्मयोनी पहाड़ी, रामशीला पहाड़ी एवं सीताकुंड पहाड़ी इन सभी पहाड़ियों के तलों में अतिक्रमण कर अवैध निर्माण का कार्य तेजी से जारी है;

(घ) क्या यह सही है कि इन पहाड़ियों के सर्वांगीण विकास के बिना गया शहर में 'हृदय योजना' पूर्ण हो सकेगी;

(ड.) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गया शहर की इन सभी पहाड़ियों को अतिक्रमण मुक्त कर सीमांकन कराने का कार्य कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

कानूनी कार्रवाई

35. **श्री केदार नाथ पाण्डेय** : क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि जिला पदाधिकारी, गया के आदेश के आलोक में चंदौती थाना कांड संख्या 330/2011 दर्ज कराया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त कांड संख्या के सभी गवाह सरकारी हैं;

(ग) क्या यह सही है कि सरकारी गवाहों के द्वारा न्यायालय में गवाही नहीं दिये जाने के कारण उक्त मुकदमे की सुनवाई लंबित है जबकि न्यायालय द्वारा नोटिस, सम्मन दिया जा चुका है, बावजूद इसके सभी सरकारी गवाह अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और न्यायालय में गवाही देने नहीं जा रहे हैं;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार चंदौती थाना कांड संख्या-330/2011 के सरकारी गवाहों को अविलंब न्यायालय में गवाही देने के लिए निदेश देना चाहती है और गवाही देने में पांच साल विलंब करने वाले सरकारी गवाहों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करना चाहती है?

थाना का निर्माण

36. **डा. दिलीप कुमार चौधरी** : क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत बहेड़ा थाना के जर्जर भवन के कारण वहां रखे अभिलेख खराब हो रहे हैं;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त थाना भवन के निर्माण हेतु पुलिस भवन निर्माण निगम को कई बार पत्र लिखा गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार दरभंगा जिलान्तर्गत बहेड़ा थाना का निर्माण यथाशीघ्र कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

मातृत्व तथा पितृत्व अवकाश

37. **प्रो. संजय कुमार सिंह** : क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि वित्त विभाग के पत्रांक-9889, दिनांक 01.12.2015 द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारियों एवं शिक्षिकाओं के मातृत्व अवकाश को 135 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि नियोजन नियमावली में नियोजित शिक्षिकाओं को 135 दिन मातृत्व अवकाश का प्रावधान किया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि नियोजन नियमावली में पुरुष शिक्षकों को 15 दिनों के पितृत्व अवकाश की सुविधा नहीं दी गयी है;

(घ) क्या यह सही है कि वित्त विभाग के आदेश पर नियमित शिक्षकों-शिक्षिकाओं और कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश 180 दिन एवं पितृत्व अवकाश 15 दिन का लाभ मिल रहा है लेकिन नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाओं को इस लाभ से वंचित होना पड़ रहा है;

(ड.) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार राज्यकर्मियों के समान नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाओं को भी मातृत्व अवकाश 180 दिन एवं पितृत्व अवकाश 15 दिन देना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

शराबबंदी की भयानक विफलता

38. **श्री बिनोद नारायण झा** : क्या मंत्री, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य में 5 अप्रील, 2016 से पूर्ण शराबबंदी के बावजूद लगभग 2 लाख शराब की बोतलें, 50 से अधिक नकली शराब की फैक्टरी एवं 16 हजार से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई है, यदि हां तो राज्य में सम्पूर्ण शराबबंदी की भयानक विफलता की सरकार जांच कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

सुनील कुमार पंवार
सचिव
बिहार विधान परिषद्

पटना
दिनांक : 02 मार्च, 2017